हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 153 देहरादून, मंगलवार, 06 दिसंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा 2 दिन में कैसे होगी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा ? 3

मुख्यमंत्री धामी ने किया मुनस्यारी महोत्सव 2022 का शुभारंभ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुनस्यारी , 6 दिसंबर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी स्थित जोहार क्लब मैदान में आयोजित मुनस्यारी महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनस्यारी महोत्सव धीरे-धीरे विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुनस्यारी के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जोहार की पावन भूमि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि मुनस्यारी के नैसर्गिक सौंदर्य ने उन्हें बचपन से ही आकर्षित किया है। मुनस्यारी जैसा रमणीक स्थल भारत में ही नहीं विश्व में मिलना मुश्किल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुनस्यारी महोत्सव के लिये 8 लाख की धनराशि दिये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर मुनस्यारी में एकलव्य विद्यालय खोले जाने, मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाये जाने, मुनस्यारी में गौ रक्षा के लिए सहयोग दिए जाने, बकरियों के चुगान की अनुमति दिये जाने एवं बोना गांव में गार्डर पुल बनाए जाने की घोषणा की। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये इनके अधिकतम उपयोग किये जाने की बात कही।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी क्षेत्र की महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि जोहार की भूमि महान समाज सेवकों, चिंतकों, भू - सर्वेक्षकों एवं पर्वतारोहियों की भूमि है। उन्होंने क्षेत्र की सभी महान विभूतियों का नाम लेते हुए उनके महान कार्यों को याद किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। मुनस्यारी क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनस्यारी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुनस्यारी क्षेत्र के विकास के लिये 66 घोषणायें की हैं जिनमें से 32 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष घोषणाओं को पूर्ण करने के लिये जनपद एवं शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के विकास के लिये चिंतन शिविरों के माध्यम से विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सभी के सहयोग एवं विश्वास के साथ 2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिये हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।

सीएम सौंपेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के नियुक्ति पत्र : डॉ. आर. राजेश कुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 6 दिसंबर , आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत 664 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सी.एच.ओ.), की नियुक्ति को लेकर रिजल्ट जारी किया जा चुका है व काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ होगी, जिसके बाद चयनित सी.एच.ओ. को माननीय मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विभाग में ताबड़तोड़ बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण मुद्दों पर दूरगामी फैसले लेकर स्वास्थ्य विभाग को नयी ऊर्जा देने में जुटे अनुभवी आईएएस और सचिव स्वास्थ्य / एन.एच.एम. मिशन निदेशक डॉ. आर. राजेश कुमार ने ये जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सी.एच.ओ. के पदों हेतु एच.एन.बी. मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से रिजल्ट जारी किया जा चुका है व काउंसीलिंग प्रक्रिया भी शीघ्र ही आरंभ होगी। नवनियुक्त सी.एच.ओ. को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा दिए जाएंगे। डॉ. आर. राजेश कुमार ने ये भी बताया कि सी.एच.ओ. की नियुक्ति के बाद सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गैर-संचारी रोग जैसे टी.बी., तंबाकू निषेध, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन), आंखों की कमजोरी, नाक, गले आदि से जुड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग में तेजी आएगी, जिससे समय पर रोगों का पता लग सकेगा व इलाज संभव होगा। सी.एच.ओ. द्वारा टारगेट पोपुलेशन जो कि मैदानी क्षेत्रों में 5,000 व पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 है में 30 से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है।

पौड़ी पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से गहरी खाई में गिरे घायलों को रेस्क्यू किया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी , 6 दिसंबर , जिला नियन्त्रण कक्ष पौड़ी के माध्यम से थाना सतपुली पर सूचना प्राप्त हुई कि कुल्हड़ बैण्ड के पास वाहन संख्या UK 15C 2901 (वैगनार) कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया है। सूचना पर जनपद के थाना सतपुली, लैन्सडाउन एवं एसडीआरएफ टीम मय राहत एवं बचाव उपकरणों के घटनास्थल पर पहुँचे तो वाहन सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था एवं वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू करते हुये स्थानीय व्यक्तियों की मदद से कड़ी मशक्कत कर गहरी खाई में उतर कर घायलों का रेस्क्यू कर सड़क तक लाया गया। उक्त वाहन को चालक दलबीर सिंह चला रहे थे, वाहन में 06 लोग बैठे हुये थे। जिसमें से 02 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, शेष 04 घायलों को पुलिस टीम राहत एवं बचाव कार्य कर 108 के माध्यम से (03 को हंस फाउण्डेशन सतपुली एवं 01 को कोटद्वार) अस्पताल पहुँचाया गया। ये हैं घायलों का नाम पता

-1- दलबीर सिंह असवाल पुत्र बलवीर सिंह असवाल, निवासी ग्राम- तछवाड़, थाना पौड़ी (उम्र-58 वर्ष)।2- सुरजीत सिंह असवाल पुत्र रामपाल असवाल, निवासी उपरोक्त (उम्र-24 वर्ष)।3- अर्पित पुत्र अनूप पटवाल, निवासी उपरोक्त (उम्र-6 वर्ष)।4- वामिका पुत्री अनूप पटवाल, निवासी उपरोक्त (उम्र-9 महीने)।नाम पता मृतकः-1- प्रीति पत्नी श्री अनूप पटवाल, निवासी ग्राम- तछवाड़, थाना पौड़ी (उम्र-32 वर्ष) 2- बिल्लू पत्नी अज्ञात निवासी रणस्वा, चौबट्टाखाल (उम्र-65 वर्ष)।

3 बीमारियों में नहीं खानी चाहिए अरहर की दाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 दिसंबर , भारत में दाल रोटी खाने की बात कही जाती है। किसी भी वर्ग या तबके में दाल रोजाना खाने में शामिल होती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये जानना कि दाल कब और किसको नुक्सान भी पहुंचा सकती है। आप जिस अरहर की फ्राई दाल को चटखारे लेकर खाते हैं उसके बारे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं किसको नहीं कहानी चाहिए अरहर की दाल भारत में दाल एक ऐसा फूड है, जिसे लोग रोजाना रोटी या चावल के साथ खाना पसंद करते हैं. हर तरह की दाल सेहत के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इनमें पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर और फॉस्फोरस जैसे कई अहम पोषक तत्वों अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं. इन्हीं में से एक है अरहर की दाल जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, साथ ही ये पेट के लिए भी अच्छी मानी जाती है. इसकी बनी सब्जी लाइट होती है इसलिए इसे डिनर में भी खाया जा सकता है. वैसे अरहर की दाल कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है.

एक्सपर्ट् कहते हैं कि शरीर में कुछ बीमारियों के होने पर इस हेल्दी सुपरफूड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. इन बीमारियों में इसे खाने से मौजूदा स्थिति और खराब हो सकती है. जानें किन लोगों को अरहर की दाल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए. शरीर में कुछ बीमारियों के होने पर अरहर की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. इन बीमारियों में इसे खाने से मौजूदा स्थिति और खराब हो सकती है. जानें किन लोगों को अरहर की दाल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए.

किडनी की बीमारी

जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या हो उन्हें भूल से भी अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए. दरअसल, इसमें पोटेशियम होता है, जो किडनी की बिगड़ी हुई हालत को और खराब कर सकता है. डॉक्टर्स का मानना है कि इस दाल से किडनी में पथरी की दिक्कत भी हो सकती है. ऐसे में इस फूड को एक्सपर्ट की सलाह पर ही खाना चाहिए.

हाई यूरिक एसिड

यूरिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है. शरीर में इसके लेवल को ठीक रखना जरूरी है. अगर यह बढ़ने लगे तो जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है. बॉडी में प्रोटीन का इनटेक ज्यादा हो, तो इससे हाई यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है. अरहर की दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है. इसी कारण हाई यूरिक एसिड में अरहर की दाल न खाने की सलाह दी जाती है.

पेट से जुड़ी समस्याएं

जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या ब्लोटिंग हो उन्हें अरहर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए. अरहर की दाल से गैस बनने की शिकायत हो सकती है. ऐसे में एसिडिटी बढ़ जाती है और ये घंटों नहीं कई दिन परेशान कर सकती है. इस हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान मरीजों को रात में भूल से भी इस दाल को नहीं खाना चाहिए.

अजब गजब : छुट्टी के लिए मां की मौत का बहाना बना रहे गुरु जी !

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 दिसंबर , यूपी हो या बिहार , इन दिनों टीचर के अजीबोगरीब लीव एप्लीकेशन वायरल हो रहे हैं। कोई टीचर लिख रहा कि 'मेरी मां बीमार है। तीन दिन बाद मर जाएगी। इसलिए छुट्टी चाहिए।' कोई लिख रहा है कि 'आज पार्टी थी, ज्यादा खा लिए। परसों तबीयत बिगड़ी जाएगी, इसलिए छुट्टी चाहिए।' इस तरह के पत्र खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए छुट्टी के लिए लिखी शिक्षकों की एप्लीकेशन

बिहार में बीते दिनों सरकारी स्कूल के टीचर छुट्टी के लिए अजीबोगरीब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इस एप्लीकेशन में भविष्य में उनके साथ होने वाली घटनाओं का जिक्र कर छुट्टी मांग रहे हैं। कोई लिख रहा है कि 5 दिसंबर को उसकी मां का देहांत होने वाला है, कोई लिख रहा है कि दो दिन बाद उसका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए तीन दिन की छुट्टी दे दीजिए। बिहार में इस तरह की अजीब लीव एप्लीकेशन मुंगेर, भागलपुर, बांका सहित कई जिलों में वायरल हुई हैं। इस तरह की चिट्ठी के जरिए स्कूल के टीचर्स विभाग के दो फैसलों का विरोध कर रहे थे। दरअसल, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए सेल्फी सिस्टम और सामान्य अवकाश के लिए पहले से सूचना देने का 29 नवंबर 2022 को आदेश दिया था।

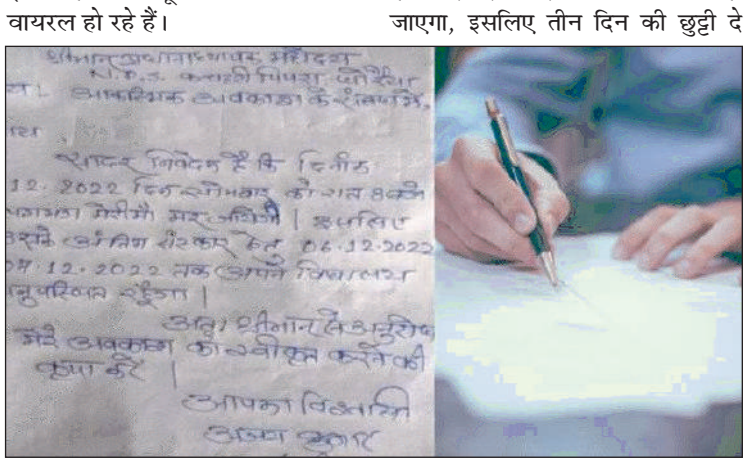

सेल्फी सिस्टम के जरिए अटेंडेंस बनाने के विरोध में शिक्षक

अगर भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर निकाय के स्कूलों की बात करें तो वहां के शिक्षक सेल्फी सिस्टम के जरिए अटेंडेंस बनाने के इस फैसले को तुगलकी फरमान बता रहे थे। इसके साथ ही शिक्षक दलील दे रहे थे कि महिला शिक्षकों को सेल्फी सिस्टम के माध्यम से अटेंडेंस बनाने में हिचकिचाहट होती है। यह निजता के अधिकार पर प्रहार है, जिसे वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेल्फी सिस्टम के इस फैसले को वापस लेने की जानकारी सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले से वायरल हो रही है।

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कहीं भी घूमें, अब बचा लेगा स्मार्टफोन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 दिसंबर , कुछ भी ड्राइव करने से पहले आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है। ऐसा नहीं करने पर आपको मोटा चालान भी भरना पड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मोटा चालान भरने से बच सकते हैं। क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस पास नहीं होने की स्थिति में भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि DL साथ नहीं होने की स्थिति में भी पुलिस आपका चालान नहीं काटने वाली है-

आज हम आपको Digilocker के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में Digilocker है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इस ऐप में अपना DL या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इस ऐप में आप Aadhaar Card, Voter ID Card, Driving License तक आसानी से सेव कर सकते हैं।

अगर कभी आपको कोई पुलिसकर्मी ड्राइव करते समय रोकता है तो आपको ये ऐप ओपन करनी होगी। ऐप ओपन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आप आसानी से बच सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह वैलिड है। अब क्योंकि स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन चुका है तो इसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, ऐसे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये ऐप रखनी है और इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होगा।कभी ऐसा होता है कि आपके पास स्मार्टफोन और DL दोनों ही मौजूद नहीं है तो आप कोर्ट का चालान कटवा सकते हैं। बस आपको कोर्ट में पेश होने के बाद डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। यहां आपको चालान भी नहीं भरना होगा। लेकिन ड्राइविंग करते समय हमेशा आपको साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। Digilocker आपको ऐसी समस्याओं से बचाता है क्योंकि आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की स्थिति में इसके खोने का भी डर लगा रहता है।

यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा 2 दिन में कैसे होगी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा ?

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हल्द्वानी , 6 दिसंबर , नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि , हाल के विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने साथर्क विपक्ष का रोल अपनाते हुए उपलब्ध समय और हर संसदीय प्रक्रिया का प्रयोग किया तो सरकार सदन में हर तरह से जिम्मेदारियों से भागती रही । उन्होंने कहा कि हाल की विधानसभा का सत्र दो दिन चला कर सरकार ने दिखा दिया है कि वह जनता के प्रति जबाबदेह नहीं है। उनका आरोप है कि जिन दो दिनों सत्र चल उसमें भी सरकार ने सदन के सम्मुख आये विषयों का जबाब देने में लापरवाही की है।

यशपाल आर्य ने तेज़ किया धामी सरकार पर हमला : नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि , सदन को विधानसभा परिचालन नियमावली और परम्पराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। इस कारण विधायकगण राज्य के अधिकांश ज्वलन्त मुद्दों को सदन में नहीं उठा पा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि , सदन में प्रश्न काल के लिए 7 दिनों को मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों में बांटा रहता है । संबधित वार को ही मंत्री गणों या मुख्यमंत्री से उनके विभागों से संबधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विधानसभा सत्र कुछ महिनों बाद होता है। यदि विधानसभा सत्र को दो दिन में ही स्थगित कर दिया जाता है तो उन दिनों के प्रश्नों को फिर उठाने का अवसर 8- 9 महिनों में ही आयेगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सोमवार के दिन सालों से सत्र आहूत नहीं है। वर्तमान में सोमवार का दिन मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के लिए तय है। जिनके पास राज्य के 40 के लगभग महत्वपूर्ण विभाग हैं। याने सोमवार के दिन सत्र आहूत न होने के कारण माननीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री से उनके विभागों के प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि ''उत्तराखण्ड संभवतया देश का पहला राज्य होगा जहां नेता सदन याने मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को सरकार विधानसभा में अपने विभागों से संबधित प्रश्नों का जबाब देने से बचा रही है।

यशपाल आर्य ने कहा कि , विपक्ष के विधायक सदन को लंबा चलाने के संबध में कई बार प्रश्न उठा चुके हैं परंतु सरकार ने कोई जबाब नहीं दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , अब प्रदेश की जनता को भी बिभिन्न माध्यमों से प्रश्न करना चाहिए कि , उत्तराखण्ड की विधानसभा में सोमवार का दिन कब आयेगा ? उन्होंने कहा कि ,विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुसार न केवल प्रश्नों के लिए बल्कि अन्य विधायी प्रक्रियाओं के लिए भी सदन में सप्ताह के दिन निर्धारित हैं जब उन दिनों सदन चलेगा ही नही तो सरकार और विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रस्तावित वे विधायी कार्य भी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि, वर्तमान सत्र शुक्रवार के दिन नहीं चलने के कारण राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी देने से संबधित प्राइवेट मेम्बर बिल सदन में नहीं आ पाया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , हाल के सत्र में सरकार की रणनीति थी कि , किसी तरह से भी दो दिन चलने वाले सदन को शोर- शराबे में उलझा कर खत्म कर दें लेकिन विपक्ष सरकार की चाल में नहीं आया। विपक्ष ने शालीनता और दृणता के साथ अपने तथ्यों और तर्को को सदन में रखा। इस कारण दो दिन का अल्प समय जो सदन चलाने के लिए मिला था उसका अधिकतम सदुप्रयोग हो गया। राज्य की चुनी हुई विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि , शोर -शराबा करने को आक्रमकता नहीं माना जा सकता है। जब आपके पास कम समय हो तो आपको विधायकों के द्वारा जनता की समस्याओं को विधानसभा के पटल में रखने का रास्ता अपनाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , विपक्ष ने कार्यस्थगन में उत्तराखण्ड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी के मामले में सरकार को बुरी तरह से घेरा । सरकार के पास बिगड़ती कानून व्यवस्था और हर भर्ती में हो रहे घोटालों से संबधित विपक्ष के आरोपों का कोई जबाब नहीं था। पिछले साल पूरे राज्य में आयी आपदा भी बड़ा मुद्दा रहा । दो दिन के प्रश्न काल में माननीय मंत्री गण विपक्ष के सवालों और तर्कों के सामने कंही नहीं टिक पाए।

अंकिता भण्डारी हत्याकांड में वीआईपी का बचाव कर रही सरकार

जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है भाजपा सरकार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 6 दिसम्बर , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य पुलिस प्रशासन पर भाजपा की राज्य सरकार के दबाव में अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड में वीआईपी चेहरे का बचाव कर जनता की आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में पुलिस एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई है तथा वीआईपी के नाम का खुलासा करने की बजाय उसके बचाव का षडयंत्र कर जनता को गुमराह कर आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दबाव में किस वीआईपी चेहरे का बचाव किया जा रहा है इसका खुलासा होना चाहिए।

पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास उठ चुका है, जरूरी है मामले की सीबीआई जांच: - करन माहरा

प्रदेश कांग्रेस करन माहरा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड में भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा पहले दिन से ही लीपापोती का काम किया जा रहा है।

भाजपा नेता से जुड़े होने के कारण पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने में जानबूझकर देरी की गई। मामले को लटकाने के लिए नियमित पुलिस और राजस्व पुलिस के बीच मामले को उलझाने का काम किया गया। हत्याकाण्ड के एक सप्ताह तक भी दोषियों की गिरफतारी नहीं की गई और गिरफ्तारी के बाद दोषियों की कई दिन तक पुलिस रिमांड भी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि हत्याकाण्ड के सबूत मिटाने की नीयत से रिसार्ट में तोड़फोड व आगजनी करवाना, पीडिता के विस्तर को स्वीमिंग पूल में डालना, पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा पहले तोड़फोड की अनुमति से इंनकार करना तथा बाद में किसके दबाव में अपना बयान बदलना पुलिस जांच पर सवाल खडे करते हैं।करन माहरा ने कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा अंकिता भण्डारी के पिता के बीच हुई वार्ता को बिना सहमति के सार्वजनिक करना। पुलिस के आला अधिकारियों के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हत्याकाण्ड से जुडे तथ्यों की फारेंसिक जांच के लिए जरूरी सबूत जुटा लिये गये हैं तथा आग लगने और डोजर चलाने से जांच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अग्निकाण्ड और तोड़फोड़ में सारे सबूत नष्ट करने के उपरान्त घटना स्थल पर पुलिस टीम द्वारा सबूतों की खोज करना आपस में विरोधाभाषी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विधानसभा सदन को गुमराह करते हुए वीआईपी के बारे में दिया गया बयान हास्यास्पद ही नहीं जघन्य हत्याकाण्ड के इस मामले को सरकारी संरक्षण की ओर भी इशारा करता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं जघन्य हत्याकाण्ड में दो महीनों में चार्जशीट दाखिल होना जैसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो प्रदेश की जनता के दिल में तीर की भांति चुभ रहे हैं जिसका पार्टी ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता सरकार से जवाब मांग रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में राज्य पुलिस की कार्य प्रणाली पहले दिन से ही संदिग्ध बनी हुई है तथा जनता को पुलिस से विश्वास उठ चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बारबार अंकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करती आ रही है।अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड मामले पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरादत्त जोशी तथा प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा सरकारी दबाव में पहले दिन से ही रवैया अपनाया गया है उससे न केवल राज्य में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है अपितु राज्य में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि राज्य में रोज नये-नये अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड में अहम सुराग जिसके आधार पर मामला खुलने में मदद मिली उसी अपने वाट्सअप मैसेज में अंकिता भण्डारी ने जिस वीआईपी के नाम का उल्लेख किया है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उस वीआईपी तथा स्पेशल सर्विस का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके।

वक़्फ़ बोर्ड और मदरसा बोर्ड में किसके मदरसे स्मार्ट, मुक़ाबला शुरू

न्यूज़ वायरस एक्सक्लूसिव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 6 दिसंबर , मदरसों पर सियासत तो आपने सुनी और पढ़ी होगी लेकिन विभागों में आगे बढ़ने की होड़ की सियासत हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के मदरसे भी तमाम मुश्किलों और समस्याओं से जूझ रहे हैं... इनकी फेहरिस्त लंबी है , लेकिन आज बात समस्याओं की नहीं करेंगे आज बात करेंगे दो अहम विभागों की , जो अपने अपने दावों के साथ इन बदहाल मदरसों को स्मार्ट बनाने की प्रतियोगिता में अब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक विभाग है उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड और दूसरा है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड , जी हां हम आपको इन दोनों विभागों के कम्पटीशन की खबर बताने जा रहे हैं , जिसकी खबर शायद अभी उत्तराखंड सरकार और खुद मुख्यमंत्री धामी को भी नहीं होगी तो चलिए आपको खबर बताते हैं।

उत्तराखंड में 419 मदरसे हैं बोर्ड में रजिस्टर्ड : लंबे समय से कांग्रेस के पास उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का जिम्मा था। लेकिन बीते दिनों धामी सरकार में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ बयान बाजी जिसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम बड़े-बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा दावा मदरसों को स्मार्ट बनाने को लेकर है। जिसमें बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि मदरसों को अब स्कूलों की तर्ज पर चलाया जाएगा। जहां स्मार्ट क्लासेज होंगी और वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके के बच्चे कॉन्वेंट की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे।

वक़्फ़ बोर्ड 5 मदरसों को बनाएगा मॉडल मदरसा : सुनने में यह बातें जितनी अच्छी लगती हैं दरअसल हकीकत में इन्हें जमीन पर साकार करना उतना ही मुश्किल काम है। यह खुद अल्पसंख्यक विभाग भी जानता है , क्योंकि मदरसों की ड्रॉपआउट संख्या ही हकीकत बयां कर देता है। यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन जब हमने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार अब्दुल यामीन से उनके रजिस्टर्ड मदरसों की सूरते हाल पूछी तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसे पहले से ही स्मार्ट है और उन्हें सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन अगर वक़्फ़ बोर्ड और उसके चेयरमैन अपने मदरसों को मॉडल मदरसा बनाने की बात कह रहे हैं तो मदरसा बोर्ड भी इस तेरा मेरा के मदरसों की चुनौती को स्वीकार करेगा। उनके बयान को एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर मानते हुए बोर्ड वक़्फ़ के मदरसों से अपने मदरसों को बेहतर बनाएगा। यानि अब मदरसा बोर्ड और वक़्फ़ बोर्ड अपने-अपने मदरसों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे।

लेकिन यहां पर आपको यह जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड में ही नहीं तमाम राज्यों में मदरसों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। बजट की रकम बोर्ड के ज़िम्मेदारों और मदरसा संचालकों की जेब में पहुँच जाती है और खाली रह जाती है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की उम्मीदें। यही नहीं मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर बेहद कम और कभी-कभी ही मिलने वाली तनख्वाह पर पढ़ाने का फर्ज निभा रहे हैं। मिड डे मील ड्रेस , किताबें , कंप्यूटर और लाइब्रेरी के नाम पर सरकारी योजनाओं और फाइलों से पैसा तो खूब निकलता है लेकिन मदरसों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि रास्ते में ही उसका हिसाब किताब सेट हो जाता है।

ऐसे में सरकार में प्रभावशाली दमखम रखने वाले वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का मदरसों की जाँच , स्मार्ट मदरसा बनाने का बयान थोड़ा जल्दबाजी और अव्यवहारिक लगता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्टसे जब हमने बात की तो उनका कहना हैं कि कौम का भला करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को सबसे पहले बुनियादी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए ना कि बड़े-बड़े बयान देकर अपनी वाहवाही करानी चाहिए। क्योंकि अगर मदरसों का भला होगा , वहां तरक्की होगी , बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो अफसर हो या नेता जनता उन्हें अपने सर आंखों पर खुद ब खुद बिठाएगी। लेकिन जिस तरह से बीते 22 सालों में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और वक़्फ़ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ों ने बरगद की तरह अपनी जड़े जमा ली है उसकी छांव में तरक्की के फूल खिलेंगे ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। नेताओं के दावे और अफसरों के इरादे तभी कामयाब होंगे जब नीयत साफ़ और नजरिया कौम की भलाई होगा।

एसएसपी श्वेता चौबे के रात्रि चैकिंग अभियान से बढ़ा अपराधियों में खौफ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

■ वारदात को अंजाम देने आए थे आरोपी, पौड़ी पुलिस की सतर्कता से धर दबोचे गए

पौड़ी , 6 दिसंबर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल, श्वेता चौबे ने अधिकारीयों को जिले में नियमित देर तार चेकिंग अभियान चलने के आदेश दिए हैं। सघन चैकिंग अभियान ने अब अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वो के विरुद्ध ठोस प्रभावी कार्यवाही के लिए शुरू किये गए मुहीम के क्रम में थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे से आये तीन शातिर बदमाशों को 3 अवैध तमंचो व 5 जिन्दा कारतूसों के साथ गिरफ्तार करते हुये उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है । जिस सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लक्ष्मणझूला पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी श्वेता चौबे कहती हैं कि आने वाले दिनों में लेट नाइट चेकिंग में कामयाबी का ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अभियान को और भी तेज़ और सख्त किया जायेगा।

एसएसपी अजय सिंह के स्मार्ट पोलिसिंग से सुलझी मर्डर मिस्ट्री, ड्रम से मिली डेडबॉडी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार , 6 दिसंबर , बीती 2 दिसंबर को थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह/ चाँद कॉलोनी में किराये के मकान में लोहे की टंकी में मिले अज्ञात शव की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली और तेजी के साथ बड़े बारीकी से पुलिस अधिकारी ने मौका मुआयना किया इसके बाद मौके से ही एसएसपी अजय सिंह ने घटना के खुलासे के लिए अलग-अलग पुलिस व सीईयू टीमों का गठन कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए।

पुलिस टीम द्वारा घटना के बारे में जानकारी करने पर मकान मालिक ने बताया कि मैने किरायेदारो का सत्यापन नही किया था और मुझे किरायेदारो के नाम पते के बारे में भी कोई जानकारी नही है। मृतक की जेब से एन0टी0एल0 कम्पनी का एक कागज मिला था जिस आधार पर पुलिस द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों से मृतक की शिनाख्त कराने पर पता चला की मृतक नितिन भंण्डारी है। शिनाख्त के आधार पर मृतक के परिजनों से सम्पर्क कर जानकारी ली गई और मामला दर्ज हो गया

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर अपराधियों के मोबाईल नम्बर मिले जिससे मोबाईल नम्बर की आई0डी0 बुलन्द शहर यूपी मिलने पर एक पुलिस टीम को तुरन्त बुलन्द शहर के लिए रवाना किया गया। जिससे पता चला कि घटना को अंजाम देने के पश्चात शातिर जयपुर ग्रेटर नोयडा, बुलन्द शहर, गाजियाबाद अलग-अलग शहरो में ठहरे हुए है। पुलिस टीम को मिली जानकारी के आधार पर उपरोक्त घटना दिनांक-27.11.2022 की रात्रि घटित कर दिनांक- 28.11.2022 को शव को छुपाने के लिए कस्बा भगवानपुर बाजार से अनाज की बड़ी टंकी खरीदकर लाये व दिनांक- 29.11.2022 को अभि0गण किराये का मकान खाली करके अपना सामान महिन्द्रा पिकअप से लेकर बुलन्द शहर चले गये। पुलिस टीम को मिली जानकारी अनुसार महिन्द्रा पिकअप चालक द्वारा बताया गया कि मेरी महिन्द्रा पीकअप दो लड़को ने अपना घर का सामान बुलन्द शहर ले जाने के लिए बुक करायी थी जो कि बुलट मोटर साईकिल में आये थे। जिसका नम्बर UK17S4986 है। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा बुलट मोटर साईकिल के नम्बर से नाम पता तस्दीक किया गया । पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त अभि0गण 1. गुलशन बेगम पत्नी जफर, 2. विधि विवादित किशोर को बुलन्दशहर उ0प्र0 से नियमानुसार पकड़ा गया। जिनकी निशांदेही पर मृतक का गेस स्लेण्डर व फ्रीज व घटना में प्रयुक्त बुलट मोटर साईकिल UK17S4986 बरामद की गयी। अन्य पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण आजाद पुत्र जफर, नौशाद पुत्र जफर निवासीगण धमेडा अड्डा वार्ड न0 32 थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उ0प्र0 को उनके किराये के कमरे कस्बा हल्दौनी, दादरी ग्रेटर नोयड़ा उ0प्र0 से दबोचा गया। जिनसे मृतक से लिए गये एक लाख दस हजार रूपये नगद व मृतक का अन्य सामान बरामद किया गया।

पर्यावरण मित्रों के कार्य पहले से और सुगम होगें : अजय भट्ट, केन्द्रीय मंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 6 दिसम्बर , केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट ने नगर निगम रूद्रपुर के सभागार में कृष्णा हॉस्पिटल द्वारा पर्यावरण मित्रों के लिए लगाये गये स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस दौरान मंत्री भट्ट ने कहा कि जो हमारे समाज एवं पर्यावरण के लिए समर्पित है ऐसे पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता कर इस शिविर का आयोजन किया है यह सराहनीय है।

उन्होने कहा कि पूर्व में सीवर लाईन की सफाई करते हुए कई लोगों ने अपनी जान गवां दी जो बहुत ही कष्टदायक है। हमारी सरकार लगातार पर्यावरण मित्रों के लिए बेहतर सुविधाऐं देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि भविष्य में नई तकनीकी के ऐसे-ऐसे उपकरण आने वाले है जिससे पर्यावरण मित्रों के कार्य पहले से और सुगम होगें। उन्होने कहा कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नही होता, हम सब एक समान है हमारी सरकार में किसी के प्रति कोई भेदभाव नही रखती। आज हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। उन्होने बताया कि आज विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो कि ऊं बिड़ला पर्वत पर बना कर भारत ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होने कहा कि हम जाति, धर्म आदि इन सब बातों से ऊपर बढ़कर सबको एक साथ आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहें है। मंत्री बताया कि मोहल्ले में जा-जा कर पीने के पानी की जांच करने वाला पहला नगर निगम रूद्रपुर है इसके लिए उन्होने मेयर रामपाल सिंह एवं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा (आईएएस) को बधाई दी।

उन्होने कहा कि जल संवर्धन का कार्य हेतु जनपद में 75 तालाब तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें से 55 तालाब तैयार किये जा चुके है शेष अतिशीघ्र तैयार होने वाले है। उन्होने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में रूद्रपुर में संजय चेतना वन का कायाकल्प करने हेतु कार्य गतिमान है जिसके लिए 20 लाख रूपये की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है, हमे बहुत जल्द रूद्रपुर में एक पर्यटन स्थल के रूप में संजय चेतना वन देखने को मिलेगा जिसमें दूर-दूर से आने वाले पर्यटक आंनन्द ले सकेंगे। इस दौरान विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, सुरेश परिहार ने भी अपने विचार रखें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी/नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, भारत भूषण चुघ, उत्तम दत्ता, अध्यक्ष जिला बार ऐसोसिएशन दिवाकर पाण्डे, योगेश वर्मा, एमडी कृष्णा हॉस्पिटल विजय अग्रवाल, डॉ0 गौरव अग्रवाल के साथ नगर निगम के पार्षदगण आदि उपस्थित थे।

तय समय सीमा से पहले ही होगा सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण : गणेश जोशी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 6 दिसम्बर , सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का मौका मुआयना कर सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्बंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा निर्माण कार्यों में इस्तामेल हो रही सामग्री में गुणवत्तता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के स्वरूप उत्तराखण्ड में सैन्य धाम निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा यह मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सैन्य धाम की मॉनिटरिंग करते रहते है। मंत्री जोशी ने कहा सैन्य धाम का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है ओर जिस प्रकार निर्माण कार्य की रफ्तार है,निश्चित ही हम तय समय सीमा से पूर्व की सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड का सैन्य धाम यहां के चार धामों की तरह ही विकसित हो। इसके लिए सैन्य धाम को भव्य रूप दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2023 के अंत से पहले ही हम सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण कर लेंगे। इस अवसर पर ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडीर, वीर सिंह,अनुराग सिंह, नीतू पुंडीर, कमलेश सती सहित कई लोग उपस्थित रहे।

तकनीकी विशेषज्ञ के ऋषिकेश में गंगा में डूबने की आशंका

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पुलिस ने बताया कि बरेली के एक 32 वर्षीय व्यक्ति के रविवार को ऋषिकेश के नीम समुद्र तट पर गंगा में डूबने की आशंका थी। अपने एक सहकर्मी की शादी में शामिल होने ऋषिकेश आए सात लोगों के समूह में शामिल राहुल मिश्रा नदी में नहाते समय तेज पानी के बहाव में बह गए.मुनि-की-रेती थाने के एसएचओ रितेश शाह ने बताया, ₹राहुल नोएडा में एक दूरसंचार कंपनी के साथ एक आईटी पेशेवर था। वह अपने दोस्तों के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए ऋषिकेश आया था।

वह नदी के तेज बहाव में बह गया था।₹रविवार को सूचना मिलने के तुरंत बाद, पुलिस के गोताखोरों ने एक तलाशी अभियान शुरू किया। सोमवार शाम तक गोताखोर उसका पता लगाने में विफल रहे। उसके माता-पिता के अनुसार, वह उनकी इकलौती संतान थी।

महंगी शिक्षा, समस्या और समाधान, जानिए

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

दिनेश कुमार सिंह, पूर्व आईएएस, उत्तर प्रदेश की कलम से

सेवानिवृत्त के उपरांत अब अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। इसे देखते हुए विभिन्न जनपदों में विभिन्न पदों पर काम करने के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर आज अपने मन की बात और विचार आपके समझ रखा रहा हूं। बीए ,बीएससी, बीबीए ,एमबीए , मेडिकल इंजीनियरिंग तकनीकी प्रशिक्षण आदि तमाम कोर्स है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है। इस कारण बहुत सारे बच्चे जो अच्छे भी हैं लेकिन उनके मां बाप फीस नहीं दे सकते हैं और वह उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं अगर वह यह शिक्षा प्राप्त करते तो उस कोर्स को करके देश के विकास में अपना योगदान कर सकते थे। लेकिन कुछ प्रतिभाएं अभाव के कारण वंचित रह जा रही है। सरकार ने जनहित में बहुत सारे काम किये है उसमें शौचालय निर्माण हो इस कारण लोटा लेकर जंगल में जाने की प्रथा समाप्त हो गई और गांव के रास्ते में जो गंदगी रहती थी वह खत्म हुई,आवास निर्माण ,मुफ्त विद्युत कनेक्शन ,सभी के बैंक में खाते खोला जाना , हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था पूरे देश के हर गांव के हर घर के लिए हो रही है यह ऐतिहासिक कार्य है जो देश को बदलने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं।अब आवश्यकता है की बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर भी व्यय किया जाए। बिना भेदभाव के हर बच्चे को चाहे किसी जाति या धर्म का किसी गरीब का हो या अमीर का हो सबके लिए उच्च शिक्षा ,प्रोफेशनल शिक्षा ,व्यवसायिक शिक्षा,भी मुफ्त में सरकारी संस्थानों व प्राइवेट संस्थानों में दी जाए इस पर आने वाले व्यय भार को सरकार अपने बजट से वहन करें।चाहे सरकारी विद्यालय हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो , संस्थान हो या प्राइवेट हो सब में मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए और सरकार अपने बजट से इसका भार वहन करें।

2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्रों में इस बात का उल्लेख हो इसके लिए अभी से हम सबको सभी दलों के जिम्मेदार लोगों के समक्ष इस बात को रखने की आवश्यकता है।।हम सब को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना है कोई भी बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वह उस शिक्षा से धनाभाव के कारण वंचित ना रहने पाए।

लोगों ने क्या-क्या गंदा नहीं बोला, मगर इन 2 ट्रांसजेंडर ने कमाल कर दिया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 दिसंबर , जिन्हे समाज से तिरस्कार और अस्वीकार्यता मिलती थी आज वो समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। जिस किन्नर को लोग एक ख़ास सोच और नज़रिये से देखते हैं उस समुदाय की दो सदस्यों ने अपने समुदाय का नाम रोशन किया है। जी हाँ दो ट्रांसजेंडरों ने बतौर डॉक्टर सरकारी सेवा में शामिल होकर इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार हुआ है। प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पॉल ने हाल ही में सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच) में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला।पर्सनल लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज को पार कर अपनी मेडिकल एजुकेशन पूरी करने वाले तेलंगाना के दो ट्रांसजेंडरों ने बतौर डॉक्टर राज्य में सरकारी सेवा में शामिल होकर इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार हुआ है। प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पॉल(Prachi Rathod and Ruth John Paul) ने हाल ही में सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच) में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। जानिए एक संघर्ष से जीत की कहानी...

मीडिया से बातचीत में प्राची राठौड़ अपने पुराने कड़वे दिनों को याद करके बताती हैं कि उन्हें इस जेंडर की वजह से शहर के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया था। प्राची ने सामाजिक कलंक और भेदभाव को याद किया, जिसे बचपन से ही सहना पड़ा था। आदिलाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से 2015 में एमबीबीएस पूरा करने वाले राठौड़ ने कहा, ₹आपकी सभी उपलब्धियों के बावजूद कलंक और भेदभाव कभी नहीं जाएगा।₹डॉ. प्राची राठौड़ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन प्रतिकूल माहौल के कारण उन्हें हैदराबाद लौटना पड़ा। हालांकि राठौड़ ने यहां एक अस्पताल में काम करते हुए इमरजेंसी मेडिसिन में डिप्लोमा किया था। प्राची राठौड़ ने तीन साल तक शहर के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में काम किया, लेकिन जेंडर(transgender) के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि अस्पताल को लगा कि इससे मरीज कम आने लगेंगे। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) उनके सपोर्ट में आया। फिर प्राची राठौड़ ने एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक में काम किया और बाद में ओजीएच में नौकरी हासिल की। हालांकि प्राची राठौड़ ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अन्य छात्रों से अपने उत्पीड़न और बदमाशी से बचा जाए? प्राची ने कहा-₹वास्तव में यह एक बुरी किशोरावस्था थी।

डॉक्टर बनने के बारे में सोचने से ज्यादा बड़ा मुद्दा यह था कि जीवन में कैसे बचा जाए और इन सभी से कैसे पार पाया जाए?₹ट्रांसजेंडरों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हुए प्राची ने कहा कि नौकरियों और शिक्षा में कुछ आरक्षण इस समुदाय को जीवन में आने में मदद करेंगे। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक पहल की गई, वैसे ही ट्रांसजेंडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 'यौन अल्पसंख्यकों-sexual minorities' पर विचार किया जाना चाहिए। डॉ. प्राची ने कहा, ₹जब आपने हमें तीसरे लिंग के रूप में कैटिगराइज्ड किया है, तो मैं सिर्फ सरकार या उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जिसने हमें अलग किया (जैसा कि) पहला लिंग कौन है और दूसरा लिंग कौन है?₹ डॉ. रूथ जॉन ने अपने साथ हुए सामाजिक कलंक और भेदभाव को याद करते हुए कहा-"मैंने अपने जेंडर के कारण बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है। डॉक्टर बनने के सपने ने मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मुझे समाज, दोस्तों और रिश्तेदारों से कई कलंक का सामना करना पड़ा। हालांकि, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं इसके लिए सुपरिटेंडेंट और सभी फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां उनके सपोर्ट के कारण हूं।"

दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के फिजोथेरिपी कैंप में मरीज़ों की उमड़ी भीड़

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 6 दिसंबर , देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निरंजनपुर में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (डीजेजेएस) एवं स्टूडेंट असोसिएशन ऑफ फिजीकल थैरेपी (एस ए पी टी इंडिया) के द्वारा विशाल निशुल्क फिजीयोथेरेपी परामर्श कैंप आयोजित किया गया। जिसमें हजारों लोगो को भारत के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान पी.जी.आई चंडीगढ के सुयोग्य कुशल डॉक्टरो द्वारा निस्वार्थ भाव से निशुल्क उपचार किया गया। पीजीआई चंडीगढ के सुपरिटेंडेंट फिजीयोथेरेपीसट डा0 बिबेक अध्या ने दीप प्रज्वलित कर व रिबन काटकर कैंप का उद्घाटन किया व सभी को फिजीयोथेरेपी का महत्व समझाया साथ ही फिजीयोथेरेपी लाभ से अवगत करवाया और संस्थान के इस दैवीय कार्य की प्रशंसा की,वही मौके पर मौजूद संस्थान की प्रचारक साधवी सुश्री अरुणिमा भारती जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया की संस्थान अध्यात्म वा संस्कार के हित के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है ,वही कोई भी मनुष्य अगर अध्यात्म रास्ते पर चलता है तो वहा जितना स्वास्थ होगा उतना ही प्रभु की भक्ति ठीक से कर पाएगा यही सोच रखते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्था समय समय पर हाथ कैंप का आयोजन करती है वही आज फिजोथेरिपी कैंप का आयोजन किया गया जिसमे डा0 बिबेक अध्या वा उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया।

वही आपको बता दे की इस कैंप में देहरादून ही नहीं देहरादून के बाहर के लोगो ने इस कैंप का फायदा लिया साथ ही इस कैंप में देश विदेश से लोग लाभ लेने पहुंचे और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में फिजोथेरिपी कैंप की काफी सहराना की।

लोगों को रंगों में बांटने का प्रयास कर रही भाजपा : आप

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 6 दिसंबर , आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने र पलटन बाजार की दुकानों के छज्जो को भगवा रंग से रंगे जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है ।

उन्होंने कहा भारत विविधताओं का देश है जहां हर प्रकार के रंग,भाषा बोली, वेशभूषा थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाती है परंतु भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता केवल और केवल भाजपा के प्रचार की है ना की जन कल्याण की ।

उन्होंने कहा भाजपा द्वारा स्मार्ट सिटी जोकि एक सरकारी योजना है की आड़ में अपने संगठन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जोकि गलत है उन्होंने कहा की पलटन बाजार की दुकानों के छज्जो का रंग भगवा ही क्यों हरा क्यों नहीं क्या रंग से किसी विशेष व्यक्ति, जाति अथवा धर्म की पहचान होती है क्या दूसरे रंग भारत के नहीं है उन्होंने कहा कि सभी रंग भारत देश के हैं एवं हमारे सनातन धर्म ने अपनाए हैं चाहे वह लाल हो सफेद हो हरा हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकीर्ण मानसिकता के चलते एवं केवल भाजपा का प्रचार करने के उद्देश्य से पलटन बाजार को भगवा रंग से रंगे जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है जो कि गलत है साथ ही यह हल्की राजनीति का उदाहरण भी है ।

रविंद्र ने आगे कहा कि सरकारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संगठन को बढ़ाने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जोकि विधि संगत एवं न्याय संगत नहीं है उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगे से रंगा है जिसमें नारंगी सफेद हरा 3 रंग है । उन्होंने भाजपा पर रंग ,जाति के भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल धर्म, रंग की राजनीति करते हुए देश को बांटने का काम किया है उन्होंने कहा आज हर व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है ऐसा पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ क्योंकि भाजपा ने अपने आईटी सेल के माध्यम से भारतीयों को बांटने का काम किया इसके लिए भाजपा ने जाति, रंग मंदिर ,मस्जिद का सहारा लिया और हमारे नेताओं द्वारा एवं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जिस प्रकार भारतीयों को एक माला में पिरोया गया था उस माला को भारतीय जनता पार्टी द्वारा तोड़ दिया गया जिससे भारतीयता बिखर रही है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर अभी भी होश में ना आई तो जिस रंग, जाति को लेकर उसने भारतीयता के टुकड़े किए हैं एक दिन वही उसके काल का कारण भी बनेगी ।

■ स्मार्ट सिटी के नाम पर मेयर कर रहे भाजपा का प्रचार : रविंद्र सिंह आनंद

संपादकीय

बदल गये हैं हमारे बच्चे

हाल में बेंगलुरु से बड़ी चिंताजनक खबर आयी. वहां लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि बच्चे स्कूल बैग में मोबाइल छिपा कर स्कूल ला रहे हैं. कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्रबंधन ने स्कूलों से छात्रों के बैग की जांच करने को कहा. खबरों के अनुसार कक्षा आठ, नौ और दस के छात्रों के बैग से सिगरेट, लाइटर, व्हाइटनर, कंडोम व शराब तक बरामद हुई. भौंचक अभिभावक यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे इतना बदल गये हैं. जब इस बारे में बच्चों से पूछा गया, तो वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करने लगे. एक छात्रा का जवाब था कि जहां वह ट्यूशन पढ़ने जाती है, वहां के लोग इसके लिए दोषी हैं. कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एसोसिएटेड प्रबंधन के महासचिव डी शशि कुमार का कहना था कि करीब 80 स्कूलों में यह जांच की गयी. स्कूलों ने फैसला किया है कि छात्रों का निलंबन समस्या का समाधान नहीं है. स्कूलों ने अभिभावकों के साथ एक साझा बैठक की और काउंसेलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया. माता-पिता से भी कहा गया है कि वे बाहर से भी बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं और इसके लिए वे 10 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल बेंगलुरु के बच्चों का मामला है, तो आप गलत सोच रहे हैं. यह हम सबके लिए खतरे की घंटी है. हम सबके चेतने का वक्त है. इसमें कोई शक नहीं है कि नयी पीढ़ी के बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन शायद आपने गौर नहीं किया कि आपके बच्चे बदल चुके हैं. विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी जब आती है, तो उसके साथ एक वातावरण और संस्कृति भी लाती है. उसकी ताकत इतनी है कि उसके प्रभाव से बचना मुश्किल है. दिक्कत यह है कि हम यह तो चाहते हैं कि पूंजी आये, लेकिन उसके साथ आने वाले वातावरण से तारतम्यता कैसे बिठाना है, इस पर कोई विमर्श नहीं होता. आप गौर करें कि आपके बच्चे के सोने, पढ़ने के समय, हाव-भाव और खान-पान सब बदल चुके है. हम या तो आंख मूंदे हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं. आप सुबह पढ़ते थे, बच्चा देर रात तक जागने का आदी है. आप छह दिन काम करने के आदी हैं, बच्चा सप्ताह में पांच दिन स्कूल का आदी है. उसे मैगी, मोमो, बर्गर, पिज्जा से प्रेम है, आपकी सुई अब भी दाल-रोटी पर अटकी है. पहले माना जाता था कि पीढ़ियां 20 साल में बदलती हैं, तकनीक ने इस परिवर्तन को 10 साल कर दिया और अब नयी व्याख्या है कि पांच साल में पीढ़ी बदल जाती है. इसका अर्थ यह है कि यदि आपके दो बच्चे हैं और उनमें पांच साल का अंतर है, तो उनके आचार-व्यवहार में भारी अंतर होगा. इस परिवर्तन में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है. मोबाइल ने सारा परिदृश्य बदल दिया है. व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तो जीवन में दाल-रोटी जैसी जरूरतों में शामिल हो गये हैं. कुछ समय पहले खबर आयी थी कि लखनऊ में एक मां ने बेटे को मोबाइल फोन पर पब्जी खेलने से मना किया, तो उसने मां की गोली मार कर हत्या कर दी. यह घटना बताती है कि हम तकनीक के कितने बंधक हो गये हैं और उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं. मुंबई में एक 16 वर्षीय बच्चे ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस के अनुसार बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और पढ़ाई के लिए कहा. इस पर गुस्से में आकर बच्चे ने एक नोट लिखा और घर से चला गया. कुछ समय बाद जब मां घर पहुंची, तो उसने बच्चे की चिट्ठी देखी कि वह आत्महत्या करने जा रहा है. पुलिस तत्काल बच्चे की खोज में जुट गयी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मोबाइल की लत से बच्चों का सोना-जागना, पढ़ना-लिखना और खान-पान सब प्रभावित हो जाता है और वे बेगाने से हो जाते हैं. टेक्नोलॉजी ने उनका बचपन छीन लिया है. अब बच्चे किशोर, नवयुवक जैसी उम्र की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय सीधे वयस्क बन जाते हैं. शारीरिक रूप से भले ही वे वयस्क नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे वयस्क हो जाते हैं. वे घर के किसी अंधेरे कमरे में हर वक्त मोबाइल अथवा कंप्यूटर में उलझे रहते हैं. अब खेल के मैदानों में आपको गिने-चुने बच्चे ही नजर आयेंगे. यह व्हाट्सएप की पीढ़ी है, यह बात नहीं करती, मैसेज भेजती है, लड़के-लड़कियां दिन-रात आपस में चैट करते हैं. इसके लिए कुछ हद तक माता-पिता भी दोषी हैं. उन्हें लगता है कि वे बच्चों को संभालने का सबसे आसान तरीका सीख गये हैं. दो-ढाई साल की उम्र के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और जल्द ही उन्हें इसकी लत लग जाती है. यह जान लें कि टेक्नोलॉजी दो-तरफा तलवार है. एक ओर जहां यह वरदान है, तो दूसरी ओर मारक भी है. कोरोना काल से पहले प्रभात खबर ने झारखंड में बचपन बचाओ आंदोलन छेड़ा था. इसमें प्रभात खबर की टीम विभिन्न स्कूलों में जाती थी, उनके साथ मनोविशेषज्ञ भी होते थे. हम भी जानना चाहते थे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं. ऐसे ही एक कार्यक्रम में मुझे भी बच्चों से संवाद करने का मौका मिला था. एक स्कूल के हॉल में लगभग 700-750 बच्चे रहे होंगे. प्रारंभिक वक्तव्य के बाद सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ.

खराब सेवाओं ने डब्ल्यूएफएच को प्रभावित किया तो अल्मोड़ा कोर्ट ने लगाई बीएसएनएल को फटकार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अल्मोड़ा जिला उपभोक्ता अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को अपने एक ग्राहक को निर्बाध ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए दंडित किया है, जिससे शिकायतकर्ता का ₹घर से कामश कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।निजी कंपनी के कर्मचारी रोहित जोशी ने बीएसएनएल से 6,925 रुपये देकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था। टेलीकॉम कंपनी ने 70 एमबीपीएस स्पीड का आश्वासन दिया था, लेकिन उपभोक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे सिर्फ 15 एमबीपीएस स्पीड मिली थी और वह भी बार-बार रुकावट के साथ।मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने बीएसएनएल को ₹मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्चश के लिए 6,000 रुपये के मुआवजे के साथ जोशी को भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया।

जोशी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 24 फरवरी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था, लेकिन इंटरनेट की धीमी गति के कारण एक दिन भी ठीक से अपना काम नहीं कर पाए। "जोशी ने कहा, ₹मेरे बॉस द्वारा अपना गुस्सा व्यक्त करने के बाद मुझे अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैं दयनीय ब्रॉडबैंड सेवाओं के कारण वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो पा रहा था।₹ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। "बाद में, जोशी ने दूसरी कंपनी से इंटरनेट सेवाओं की सदस्यता ली और बीएसएनएल से अपना पैसा वापस करने को कहा।

ब्रॉडबैंड स्पीड रिकॉर्ड और बीएसएनएल को भेजी गई शिकायतों जैसे सबूतों को देखने के बाद, अदालत ने बीएसएनएल को केस दर्ज करने की तारीख से 6% के ब्याज के साथ जोशी का पैसा वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी को ₹मानसिक उत्पीड़नश के लिए जोशी को 3,000 रुपये और मुकदमेबाजी शुल्क के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

हरिद्वार : नाबालिग सौतेली बेटी से रेप के आरोप में शख्स को 20 साल की जेल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) कुसुम शनि ने अपनी 10 साल की सौतेली बेटी से रेप के मामले में हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। लड़की की मां ने कुछ साल पहले पति की मौत के बाद उससे शादी कर ली थी।अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भूपेंद्र कुमार चौहान के अनुसार, 7 मार्च, 2021 को, उस व्यक्ति ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार किया, जब उसकी पत्नी देहरादून में अपनी बहन के यहाँ गई थी और लड़की और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे।₹उस व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था जिसके बाद उसने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए घर छोड़ दिया। अगले दिन, जब महिला वापस आई, तो उसकी बेटी ने आपबीती सुनाई। सजायाफ्ता पति ने इस बारे में बात करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।₹ एडीजीसी चौहान ने कहा, ₹वे एक गरीब परिवार हैं और महिला ही एकमात्र कमाने वाली है जबकि पुरुष नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल है। अपनी बेटी के साथ क्या हुआ यह जानने पर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया।एडीजे कोर्ट ने जिला न्यायपालिका सेवा प्राधिकरण को लड़की को उचित अनुग्रह राशि देने का भी आदेश दिया।

देहरादून में लैब टेक्नीशियन की मौत मुख्य आरोपी की पत्नी गिरफ्तार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

28 वर्षीय लैब टेक्नीशियन विपिन रावत की मौत के एक दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी विनीत अरोड़ा की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया।देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने को कहा, ₹यह विनीत की पत्नी पार्थेविया थी, जिसने घटना की रात रावत की एक महिला मित्र पर भद्दी टिप्पणी करने के बाद सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी।₹ विनीत ने 25 नवंबर को बेसबॉल के बल्ले से रावत के सिर पर वार किया था और शहर के एक अस्पताल में उनकी मौत के बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।इलाके के सीसीटीवी फुटेज में पार्थेविया को पहले रावत की महिला मित्र को मारते हुए दिखाया गया है। जल्द ही, उसका पति उसके साथ हो गया और रावत पर हमला कर दिया, "एसएसपी कुंवर ने कहा।लोकप्रिय दून भोजनालय के बाहर कहासुनी के दौरान बेसबॉल के बल्ले से पीड़ित को मारा गया रावत अपनी महिला मित्र की ओर से दंपति से माफी मांगकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मामला शांत हो गया था और दोनों पक्ष घर जाने के लिए मुड़े तभी विनीत ने अचानक अपनी कार से बेसबॉल का बल्ला निकाला और रावत के सिर पर मारा और फिर अपने दोस्त निखिल राणा की पीठ पर मारा। राणा को मामूली चोटें आईं, रावत जमीन पर गिर गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने के लिए रावत की महिला मित्रों में से एक पर।₹रात का खाना खाने के बाद, रावत और दो महिलाओं सहित उनके तीन दोस्त, भोजनालय के बाहर खड़े थे। दो महिला मित्रों में से एक धूम्रपान कर रही थी, जब पार्थेविया, जो उनके पास खड़ी अपनी कार के अंदर बैठी थी, ने धूम्रपान करने पर उस पर भद्दी टिप्पणी की। जब महिला ने वापस जवाब दिया, तो पार्थेविया कार से बाहर आया और उसे मारना शुरू कर दिया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जल्द ही, उसका पति उसके साथ हो गया, जिसके बाद चीजें बढ़ गईं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ₹पुलिस अधिकारी ने कहा।एसएसपी कुंवर ने कहा कि पुलिस अरोड़ा दंपत्ति के साथ कार में मौजूद एक अन्य दंपत्ति के शामिल होने की भी जांच कर रही है। ₹हालांकि, रावत के दोस्तों सहित चश्मदीदों ने पुलिस को बताया था कि अन्य दंपति हमले में शामिल नहीं थे। अगर जरूरत पड़ी तो उनसे मामले में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल बेसबॉल बैट बरामद कर लिया है और उनकी कार जब्त कर ली है। एसएसपी कुंवर ने कहा।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 39 गो सदनों के लिए 10 करोड़ 48 लाख के चेक बांटे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 6 दिसंबर , प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 39 गो सदनों हेतु गोवंश भरण पोषण हेतु 10 करोड 48 लाख की धनराशि के चेक वितरित किये। विभागीय स्तर पर निराश्रित गो वंश को शरण देने के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को वार्षिक गो सदन वितरण एवं सम्मान की व्यवस्था के तहत यह धनराशि पशुपालन मंत्री द्वारा वितरित की गई। प्रदेश में शरणागत गोवंश की वार्षिक औसत संख्या 9559 है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गोवध एवं गोतस्करी पर प्रभावी रोक तथा समस्त गोवंश का संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है।

अलाभकर गोवंश निराश्रित, अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार तथा गोतस्करों से जब्त किये गये गोवंश का संरक्षण गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने की परम्परा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को गोवंश भरण पोषण एवं निर्माण मद में आशिक राजकीय अनुदान निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रस्ट एक्ट अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत गैर सरकारी गोकल्याण संस्थाओं द्वारा अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने का कार्य किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले इन गोसदनों को राजकीय मान्यता तथा अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने गैर सरकारी गोकल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित सभी गोसदनों से अपेक्षा की कि वे आंशिक राजकीय सहायता के अतिरिक्त जनसहयोग, गोबर, गोमूत्र एवं अन्य पंचगव्य उत्पादों के माध्यम से भी यथासंभव अधिकाधिक आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रयास करें। कैबिनेट मंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा भी नगर निकायों के माध्यम से कांजी हाउस गोशाला शरणालयों की स्थापना हेतु कार्ययोजना प्रारम्भ की गई है तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में 25-25 ग्रामों के समूह के माध्यम से कांजी हाउस गौशाला शरणालयों की स्थापना प्रस्तावित है। इस अवसर पर पं० राजेन्द्र अणथ्वाल, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग, राजीव गुप्ता उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोकसेवा अधिकरण, डा० प्रेम कुमार, निदेशक पशुपालन डा० लोकेश कुमार, अपर निदेशक पशुपालन विभाग, डा०डी०सी० गुरुरानी, संयुक्त निदेशक, डा० नीरज सिंघल, संयुक्त निदेशक, डा० शरद भण्डारी, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, डा० राकेश नेगी, मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद, डा० रमेश नितवाल संयुक्त निदेशक उपस्थित थे।

सावधान : ट्रैफिक रूल फॉलो न करने वालों पर बरस रही है आसमान से आफ़त, अब आपको 'ऊपर वाला' देख रहा है

रिपोर्ट: एम. फ़हीम 'तन्हा'
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

दुनिया के देशों में अगर देखें तो भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा अमेरिका कनाडा ब्रिटेन तमाम ऐसे बड़े विकसित देश है जहां लोकतंत्र फल फूल रहा है। लेकिन भारत एक मायने में और दुनिया के सभी देशों से बड़ा है और महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक रूप से संविधान बड़ा और मजबूत है । दूसरा यह कि यहां सबसे ज्यादा कानून है। कहावत है कि सबसे ज्यादा कानून वहां बनाने पड़ते हैं जहां के लोग नियमों का पालन करने में लापरवाह होते हैं । इस कहावत को भारत के संदर्भ में अगर आप परखना चाहे तो कई कानून या कई नियम आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन पर आपको हंसी भी आएगी और ऐसा भी लगेगा कि आखिर जो नियम अपने आम जीवन में नागरिकों को स्वयं अपनाने चाहिए , जिस मैनर्स को अपनाना चाहिए उसके लिए भला कानून बनाने की जरूरत क्या है? उदाहरण

के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने, सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी-सिगरेट पीने से रोकने के लिए भी कानून बने हुए हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे भारत में जहां इतना बड़ा मजबूत लोकतंत्र है वहां पर तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको इन छोटी-छोटी गलत आदतों को ना करने के लिए , या गलतियां ना करने के लिए भी कानून के सहारे से समझाना पड़ता है । आप सोच रहे होंगे कि यह बात आखिर हम क्यों कह रहे हैं , या यह उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? तो आइए अब असली खबर पर आते हैं।

भारत में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है टू व्हीलर और फोर व्हीलर की संख्या लगातार बढ़ रही है । बढ़ते हुए वाहनों के हिसाब से शहरों की सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है । और बड़े हाईवे भी बनाए जा रहे हैं । लेकिन वाहनों को ठीक से चलाना, वाहनों को ठीक से पार्क करना, वाहनों के चलाने के नियमों का पालन करना, अभी भी बहुत से लोग मजाक समझते हैं , और उनके प्रति पूरी लापरवाही बरतते हैं । अब ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के लिए नई-नई तकनीक का सहारा लेकर उत्तराखंड पुलिस द्वारा उनको पनिशमेंट करना शुरू कर दिया गया है । देहरादून में अगर आप वाहन चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे या गलत तरीके से पार्किंग करेंगे , गलत तरीके से गाड़ियां चलाएंगे, रेड लाइट को पार करेंगे , बेतरतीब गाड़ी ट्रैफिक में चलाएंगे या पार्क करेंगे तो इन सब के लिए अब आपको पनिशमेंट मिलने लगी है। और यह पनिशमेंट ना सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मिल रही है अब नई तकनीक का सहारा लेकर आसमान से भी ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है।

देहरादून पुलिस ने ड्रोन आसमान में उतारकर गलत रूप से वाहन चलाने वालों या ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करने वालों के पीछे ड्रोन लगा दिया है। यह ड्रोन सभी ट्रैफिक पर नजर रखता है और इसके जरिए उन लोगों को चालान भेज दिए जाते हैं। करीब 12 दिनों में 150 वाहन चालकों को चालान भेजे जा चुके हैं। अब आप सावधान हो जाइए और ये मत सोचिए कि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं खड़ा है तो आप गलत जगह गाड़ी पार्क करके बच जाएंगे, याद रखिये कि आपको 'ऊपर वाला' देख रहा है।

मुख्य सचिव ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 की बैठक ली

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 6 दिसंबर ,मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान विभिन्न प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ईएफसी के लिए पूर्ण योजना के साथ प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर विभाग मात्र बिल्डिंग स्ट्रक्चर के प्रस्ताव लेकर ईएफसी में प्रस्ताव भेज रहे हैं।

इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बिल्डिंग प्लान, प्रोजेक्ट का उद्देश्य, संरचना एवं पदों के सृजन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्लान के साथ समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव भेजे जाएं। व्यय वित्त समिति की बैठक में सिंचाई विभाग की लगभग 3565.28 लाख की लागत के भगवानपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया में ड्रेनेज मास्टर प्लान और डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनेज सिस्टम की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इसके लिए पूर्व से ही प्रत्येक पहलू पर विचार कर लिया जाए। उद्यान विभाग की श्रेणी 'बी' के अंतर्गत लगभग 1824.48 लाख की एकीकृत सिंचाई व्यवस्था, औद्यानिक यंत्रीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं 1120.00 लाख की रामनगर नैनीताल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कॉलेज अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्यान में बहुत ही अधिक सम्भावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।बैठक में शहरी विकास के देहरादून तरला नगल में सिटी पार्क के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। मुख्य सचिव ने सिटी पार्क में हरियाली का विशेष ध्यान रखने की बात कही। कंक्रीट के न्यूनतम प्रयोग की बात कहते हुए उन्होंने पाथ-वे को बुजुर्ग लोगों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें इसमें चलने में समस्या न हो।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, हरिचन्द्र सेमवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।